कुल उत्पादन क्रमशः 49.584 एम एमटी, 51.682 (अस्थायी) और 25.087 एम एम टी (अस्थायी) है।

(ख) वर्ष 1993-94 के लिए पेट्रोलियम उत्पादों की मांग लगभग 60.760 एम एम टी होने की आशा है।

(ग) उत्पादों के आयात पर व्यय को कम करने के लिए वर्तमान रिफाइनरियों का विस्तार करके तथा संयुक्त उपक्रम तथा निजी क्षेत्र दोनों में नई ग्रासरूट रिफाइनरियों की स्थापना करके शोधन क्षमता को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण को बढ़ावा देने के अतिरिक्त कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कई तेल और गैस क्षेत्र विकास परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। सरकार ने निजी कम्पनियों द्वारा विकास के लिए कुछ तेल/गैस क्षेत्रों को प्रस्तावित किया है।

(घ) और (ङ) 1992-93 के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों और कच्चे तेल के आयात पर लगभग 17045.46 करोड़ रुपए के विदेशी मुद्रा का खर्च हुआ तथा वर्ष 1993-94 में लगभग 21917 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा खर्च होने का अनुमान है। वर्ष 1994-95 के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता का इस समय आकलन करना जल्दबाजी होगी।

Meeting of the Foreign Ministers of India and Pakistan

*199. SHRI S.S. SURJEWALA: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) what is the agenda for the proposed meeting of the Indo-Pak foreign Ministers likely to take place this month;

(b) whether Government have agreed to negotiate on the status of the Kashmir; and

(c) whether the active help being rendered to the extremists activities by Pakistan particularly in Punjab and Kashmir would be part of the agenda to be discussed?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI R. L. BHATIA): (a) The Foreign Ministers of India and Pakistan met at Dhaka on 4th December, 1993 during the SAARC Council of Ministers Meet. At their meeting, the two Foreign Ministers exchanged views on bilateral issues.

(b) It is envisaged that at the Foreign Secretary-level talks between India and Pakistan scheduled to be held in Islamabad from 1—3 January, 1994, comprehensive discussions on matters of mutual interest including all aspects of the Jammu and Kashmir issue would take place.

(c) Pakistan's support to terrorist activities directed against India remains an issue of continuing concern to India. This issue has and will be taken up with Pakistan by Government at every opportunity.

Poaching incident in National Parks and Wildlife Sanctuaries

200. DR. SANJAYA SINGH: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS and be pleased to state:

(a) what is the number of poaching incidents took place in National Parks and Wildlife Sanctuaries during the last 3 years; year-wise;

(b) if so, how many persons have been arrested in such cases;

(c) whether it is a fact that the Security staff posted in those National Parks are not equipped with the latest arms and as a result thereof they are not in a position to challenge the poachers; and

(d) if so, what are the reasons therefor and by when latest arms are proposed to be provided to the security staff?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) and (b) As per the reports from 18 States/Union Territories 122 poaching cases in National Parks and Sanctuaries have been reported during the last 3 years, i.e., 1989-90, 1990-91 and 1991-92. Year-wise details are placed below as

Statement, *(see below).* Information regarding arrest of persons is not compiled by this Ministry but by the State Governments.

Statement

Poaching cases reported during the last three years

States	1989-90	1990-91	1991-92
Anthra Pradesh	1	N.A.	N.A.
Arunachal Pradesh	3	1	N.A.
Bihar	11	1	N.A.
Goa	N.A.	N.A.	Nil
Gujarat	8	4	6
Himahcal Pradesh	10 cases	reported	
Maharashtra	1	4	4
Manipur	N.A.	Nil	Nil
Meghalaya	Nil	Nil	Nil
Nagaland	Nil	Nil	Nil
Rajasthan	N.A.	12	6
Sikkim	Nil	Nil	Nil
Tamil Nadu	10	6	4
Uttar Pradesh	12	7	1
A & N Island	Nil	Nil	Nil
Dadra Nagar	Nil	Nil	Nil
Daman Diu	Nil	Nil	Nil
Lakshadweep	Nil	Nil	Nil
	Total: 122 cases reported		

(c) and (d) Financial Assistance is provided to the State Governments for strengthening antipoaching infrastructure in the protected areas under the Centrally Sponsored Schemes, namely, 'Development of National Parks and Sanctuaries', 'Project Tiger' and 'Project Elephant' which, among other things is utilised for providing arms and ammunition for the staff posted in the protected areas. Almost in all the sanctuaries and National Parks the key protection staff are provided with 12 bore guns. In important sanctuaries and National Parks the Staff have also been provided with Rifles. In a few states the Forest Rangers in some areas have also been provided with revolver. Where the problem is acute, help of forest protection force police and para military forces is taken for combating the menace of poaching and smuggling.

Assistance was also provided to the State Governments for the purpose under the schemes of 'Control of Poaching and Illegal Trade in Wildlife'. The scheme, alongwith resources, have been transferred since 1992-93 to the State Governments on the recommendations of the National Development Council.

वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित किया जाना

1585. **श्री नारायण प्रसाद गुप्ता:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार ने वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने के संबंध में कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश के कितने वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे और कितने प्रस्तावों को स्वीकृति दी जा चुकी है;

(ग) क्या यह सच है कि वन ग्रामों की स्थापना वन (संरक्षण) अधिनियम लागू होने के पूर्व हो चुकी थी और इनका गैर-वानिकी उपयोग भी उक्त अधिनियम लागू होने के पूर्व ही प्रारम्भ हो चुका था, क्या भारत सरकार ने राज्य सरकारों को इनके नियमितीकरण के लिये अधिकृत किया है; और

(घ) क्या मध्य प्रदेश से इस आशय के कुछ विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें वन ग्रामों की स्थापना के संबंध में आदेशों का हवाला देते हुए यह अनुरोध किया गया है कि इस संबंध में केन्द्रीय सरकार स्तर पर कार्यवाही किये जाने के बजाय राज्य प्रशासन को आगे कार्यवाही करने की अनुमति दी जाये, यदि हां, तो इस विषय में कब तक आदेश जारी कर दिये जायेंगे?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) इस मंत्रालय, द्वारा 18.9.1990 को जारी मार्ग-निर्देशों के अनुसार वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबंधों के अनुसार अपेक्षित वन भूमि को अधिसूचना से निकालने के पश्चात् वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित किया जा सकता है।

(ख) मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत 216 वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने के लिए 10 प्रस्ताव भेजे हैं। अभी तक वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने संबंधी मध्य प्रदेश के किसी भी प्रस्ताव को अनुमोदित नहीं किया गया है।